would be invidious and unjustified. The Third Pay Commission which is currently engaged in a review of the conditions of service, emoluments etc. of the Central Government employees is likely to go into such matters and their recommendations have to be awaited before any change in the present policy can be considered.

Non-Implementation of Judicial Award of the National Industrial Tribunal dated 3-3-1960 Regarding Appointments etc. In Cantonment Boards

1971. SHRI AMARNATH VIDYALANKAR : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether all the directions contained in the Judicial Award of the National Industrial Tribunal dated the 3rd March, 1960, in respect of framing of rules for making appointments, promotions and transfers from one Cantonment to another have been fully implemented;

(b) which decisions still ramain unimplemented; and

(c) the reasons for non-implementation and the period by which the same are likely to be implemented ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) to (c). Presumably the Hon'ble Member is referring to the Award published on 4th March, 1960 (not 3rd March 1960) relating *inter alia* to framing of rules for appointment, promotion and transfer of Cantonment Board employees. It has not been possible fully to implement the directions contained in the Award. Initially it was considered that rules for recruitment, promotion and transfer of Cantonment Board employees in accordance with the direction and recommendation of the Tribunal could not be framed without amending the Cantonments Act, 1924. This amendment was proposed to be undertaken along with a number of other amendments in view. It is since considered that even within the ambit of the present Cantonments Act, it is possible to give effect to the directions/ suggestions of the Tribunal on the points in question. The proposed amendments to the Rules were published for the second time in November 1969 inviting objections and suggestions in regard thereto. The Rules have now been finalised and will be published shortly.

राजकोट में मुद्रा के रूप में कूपनों का प्रचलन

1972. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात राज्य के राजकोट तथा अन्य नगरों में वहां के कुछ संस्थानों द्वारा समान्तर मुद्रा के रूप में कूपनों का प्रचलन किया जा रहा है जिससे राजकोट में किसी भी स्थान पर सामान खरीदा जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सरकार को मालूम है कि गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट तथा भाव-नगर नगरों में होटलों के मालिक, दुकानदार तथा यात्री वाहनों के चालक छोटे सिक्कों के बजाय कूपन बांट रहे हैं। लेकिन उन्हें सामान्तर मुद्रा का नाम नहीं दिया जा सकता क्योंकि लोग उन कूपनों को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं हैं और न ही उन कूपनों को जारी करने वाले उन्हें स्वीकार करने के लिये बाध्य हैं। इसलिये उनका चलन निश्चित रूप में परस्पर परिचित थोड़े से लोगों तक ही सीमित है।

(ख) ऐसे उपाय किसी कानून का उल्लंघन नहीं होते वे स्थानीय रूप में छोटे सिक्कों की कमी के लक्षण हैं। इसलिये सरकार का पहला काम छोटे सिक्कों की ओर अधिक सप्लाई करके ऐसी कमी को दूर करना है जिससे ऐसे उपायों की जरूरत ही न रहे। गुजरात राज्य में 1971 के दौरान छोटे सिक्कों की सप्लाई पिछले वर्ष की सप्लाई किये गये सिक्कों की तुलना में 62 प्रतिशत अधिक थी। अहमदाबाद नगरपालिका परिवहन सेवा को छोटे सिक्कों की सप्लाई का साप्ताहिक कोटा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक की अहमदाबाद शाखा ने वास्तविक लेन-देन के लिये छोटे सिक्कों की जरूरत वाले विभिन्न संगठनों के लिये छोटे सिक्कों के कोटे निर्धारित कर दिये हैं। बैंक विभिन्न व्यावसायी संस्थाओं में वितरण के लिये गुजरात वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल अहमदाबाद को भी प्रति सप्ताह 35,000 रुपये के मूल्य के छोटे सिक्के दे रहा है।

आयकर की बकाया राशि

1973. **श्री हुकम चन्द कछवाय:** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में आयकर की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) आयकर की राशि को वसूल करने के लिये सरकार भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) दिनांक 31 मार्च, 1972 की स्थिति के अनुसार देश में वसूली के लिये आयकर की शुद्ध बकाया रकम 438.60 करोड़ रु० थी।

(ख) बकाया रकम को वसूल करने की समस्या पर सरकार का ध्यान निरन्तर रहता है। जब कभी नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनको हल करने के लिये प्रयत्न किये जाते हैं। इस संबंध में सरकार, वांचू समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार कर रही है।

Flights Undertaken by Prime Minister During Elections to State Assemblies

1974. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI:

SHRI ONKAR LAL BERWA:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the total number of trips made by the Prime Minister in the Indian Air Force planes during the Elections to the State Assemblies held in 1972;

(b) the total expenditure incurred on the Indian Air Force planes used by the Prime Minister;

(c) whether Government have since received the payment thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) to (d). During the period 13th February to 9th March, 1972, the Prime Minister made 151 trips in Indian Air Force planes. No separate costing is done for such flights, but recoveries are made at the rates prescribed under the rules. The amount recoverable under the rules in respect of these flights comes to Rs.4.97 lakhs (approximately). An amount of Rs. 2,89,568.25 has already been credited to the Defence Services Estimates and action is being taken to recover the balance.

Loan from Nationalised Banks to Foodgrain Traders of Assam

1975. SHRI ROBIN KAKOTI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether foodgrain traders of Assam have been given any loans by nationalised banks for trade in foodgrain; and

(b) if so, the total amount of loans given for this purpose after the Nationalisation of Banks, District wise?